RNI : UAHIN/25/A3210

आवाम इंडिया

हिन्दी साप्ताहिक

वर्ष: 01 | अंक: 10 देहरादून, शुक्रवार 19 जून 2026 | मूल्य 2 रुपये | पृष्ठ: 8 | www.aawamindia.com

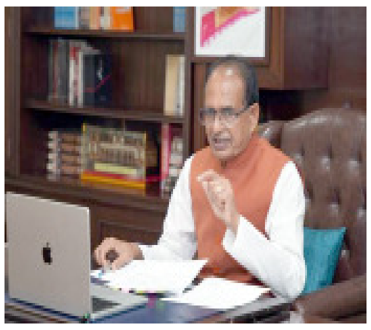

कैबिनेट बैठक : 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तराखण्ड बना पूर्ण साक्षर राज्य

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।

सचिवालय में आज धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गौ-वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण और दुग्ध वृद्धि की पायलट परियोजना को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। चार धाम यात्रा में प्रयोग किए जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं के बीमा प्रीमियम की 20 प्रतिशत धनराशि राज्य सेक्टर के अंतर्गत वहन किए जाने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। शेष 80 प्रतिशत धनराशि पशु स्वामियों द्वारा दी जाएगी। इस योजना के तहत वर्ष 2026 की यात्रा के लिए अनुमानित 15,000 पंजीकृत घोड़े-खच्चरों को कवर किया जाएगा, जहां प्रति पशु ₹ 70,000 की कीमत पर 5 प्रतिशत बीमा दर के अनुसार कुल 525 लाख के प्रीमियम में से राज्य सरकार अपने हिस्से के 105 लाख का वित्तीय भार उठाएगी।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में प्राप्त 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत अधिसूचना संख्या 244 दिनांक 18.08.2024 के प्रख्यापन तथा एतत् संबंधी शासनादेश संख्या 139, दिनांक 24.11.2024 के जारी होने के मध्य उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति तीन भर्ती परीक्षाएं कनिष्ठ सहायक एवं अन्य पदों हेतु भर्ती परीक्षा, 2024, आरक्षी जनपदीय पुलिस (पुरूष) तथा आरक्षी पीएसी /आईआरबी (पुरूष) भर्ती परीक्षा, 2024 एवं अपर निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक एवं अन्य पदों की भर्ती परीक्षा, 2024 में आवेदन जमा किए जाने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्धारित प्रारूप पर राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्युमेंट वैरिफिकेशन के दौरान एक बार के लिए अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया गया।

मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में अत्याधिक वृद्धि से बिटुमिन की कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप मात्र बिटुमिनस् कार्यों हेतु

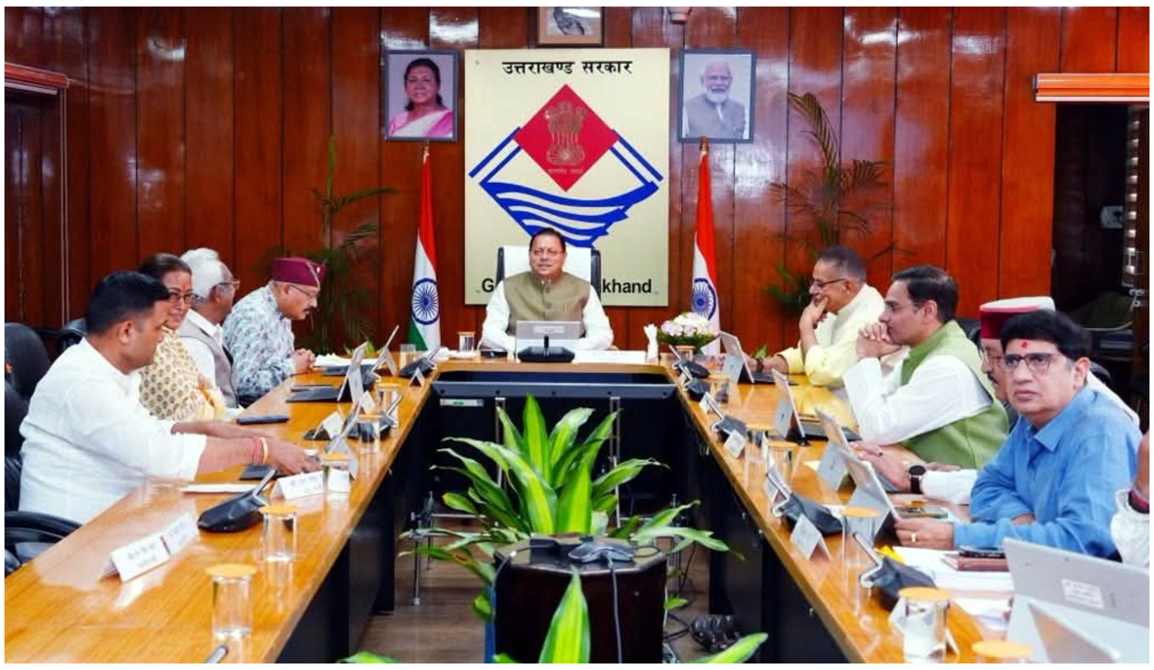

कार्यहित में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में दिनांक 01-04-2026 से पूर्व गठित बिटुमिनस् कार्य के ऐसे सभी अनुबन्धों, जिनमें अनुबन्ध की समयावधि उपलब्ध है तथा बिटुमिनस् कार्य किए जाने शेष हैं, में संशोधन करते हुए दिनांक 01-05-2026 से दिनांक 30-06-2026 तक की अवधि के लिए मात्र बिटुमिनस् कार्यों हेतु मूल्य समायोजन किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने पर सहमति प्रदान की गई है।

आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) से संबंधित शासन की अधिसूचना संख्या: 112/दिनांक 31 मार्च, 2026 के परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में अंकित उपकर को वैट अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत वैट गणना का भाग बनाए जाने एवं नियम 12.2 सम्बन्धी तालिका में होलोग्राम शुल्क के दोहराव की स्थिति उत्पन्न होने के दृष्टिगत उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट 'ख' के क्रमांक 4 में सम्मिलित किए गए होलोग्राम शुल्क को विलोपित करते हुए संशोधन/प्रतिस्थापन किए जाने पर मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई।

ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टीआईईएस) योजनान्तर्गत सगन्ध तेलों/उत्पादों में मिलावट की जांच हेतु सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई में अत्याधुनिक एएमएस मशीनों के संचालन के लिए पीएमयू गठिन किए जाने हेतु पांच पद सृजित करने पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की।

उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही अन्तर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को लेकर मंत्रिमंडल में विस्तार से चर्चा की गई। इस क्रम में अनुभवी संस्था का चयन किया जाना अति आवश्यक है। इस रैली में कुल 120 से अधिक एन्ट्री को शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 25 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 25 एशिया कॉस कन्ट्री रैली, 20 क्लासिक कार रैली, 50 भारतीय राष्ट्रीय रैली चौम्पियनशिप शामिल हैं। हिमालयन कार रैली के आयोजन हेतु संस्था का चयन एकल स्रोत के माध्यम से किए जाने को लेकर मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2026 के क्रम में उपनल के माध्यम से योजित कार्मिकों को समान कार्य हेतु समान वेतन प्रदान किए जाने हेतु पूर्व में निर्धारित पात्रता की कट ऑफ डेट (12.11.2018) को संशोधित कर सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2024 तिथि निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गई।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2024 के अनुपालन में उत्तराखण्ड कारागार नियमावली, 2023 में अभ्यस्त अपराधी, जिसे इस नियमावली के प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात् उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध, अधिनियम, 1952 की अनुसूची में उल्लिखित किसी एक या अन्य अपराध के लिये कम से कम तीन पृथक-पृथक अवसरों पर मौलिक अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो और ऐसा दण्डादेश अपील अथवा पुनरीक्षण में अपास्त न कर दिया गया हो, में संशोधन हेतु उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तराखण्ड की संरचना में अधीनस्थ कारागारों हेतु कारापाल के कुल 14 पद सृजित हैं, जो स्थायी उप कारापालों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पद हैं। वर्तमान में कारागार विभाग में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जेल कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1980) अनुकूलन उपान्तरण आदेश, 2002 लागू है। उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात कारागार विभाग में पृथक से कारापाल सेवा नियमावली को प्रख्यापित नहीं किया गया है। विभागीय एवं कर्मचारी हित में उत्तराखण्ड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई।

राज्य में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम निर्धारण एवं परीक्षा संचालन हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद को विधि द्वारा गठित संस्था के रूप में स्थापित करने के संबंध में उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2014 प्रख्यापित किया गया। उक्त अधिसूचना के कार्यान्वयन हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विनियमावली, 2023 प्रख्यापित की गई, जिसमें कतिपय संशोधन/परिवर्तन के दृष्टिगत उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता के मानकों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने सहमति प्रदान की। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न चिकित्सालयों में लम्बित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। वर्षों से लंबित 'किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना' पर संबंधित राज्यों में सहमति बनाए जाने पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

कैबिनेट के बड़े फैसले :-

- उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी।
- सड़क बनाने के इस्तेमाल होने वाले कोलतार की उपलब्धता ना होने की वजह टेंडर की अनुबंध समय बढ़ाया गया।
- उत्तराखंड मे पूर्णतः साक्षरता घोषित करने को लेकर कैबिनेट में मंजूरी।
- आबकारी नियमावली में संशोधन, अब वेट और सेस में लगाने वाले दोहरे टैक्स को खत्म किया गया।
- कृषि विभाग में सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में परफ्यूम की जांच के लिए बनायी जाएगी प्रयोगशाला।

सचिवालय शासन व्यवस्था की आत्मा और जनविश्वास का प्रमुख केंद्रः मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग कर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सचिवालय संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक जोशी, उपाध्यक्ष राकेश जोशी एवं संजय कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष श्रीमती प्रमिला टम्टा, महासचिव राजेन्द्र रतूड़ी, सचिव अतुल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव दिव्यांशु डोभाल एवं सुरेन्द्र सिंह रावत, संप्रेक्षक श्रीमती रीना मखनवाल, कोषाध्यक्ष रमेश सिंह बर्त्वाल तथा प्रचार सचिव दीपक बिष्ट सहित समस्त नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सचिवालय केवल एक भवन नहीं, बल्कि प्रदेश की शासन व्यवस्था की आत्मा और जनविश्वास का प्रमुख केंद्र है। यहीं से नीतियों का निर्माण होता है, जनकल्याणकारी योजनाओं को दिशा मिलती है और प्रदेश के विकास की रूपरेखा तैयार होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी विकसित उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण सहभागी है। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं को धरातल पर उतारने तथा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में सचिवालय परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी शासन एवं जनता के बीच विश्वास के मजबूत सेतु के रूप में कार्य करते हैं। उनकी कार्यकुशलता, कर्मनिष्ठा और समर्पण से सरकार की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रारंभ से ही शासन व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए समाधान की दिशा में कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत, प्रेरित और संतुष्ट कर्मचारी तंत्र सुशासन की सबसे बड़ी शक्ति होता है। शासन और कर्मचारी जब टीम भावना के साथ कार्य करते हैं तो विकास कार्यों को गति मिलती है और जनता का विश्वास शासन व्यवस्था पर और अधिक मजबूत होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, तकनीक आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने और ई-गवर्नेंस को सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आम नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध हों। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सचिवालय परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में उत्तराखंड सचिवालय बेहतर कार्य संस्कृति, आपसी समन्वय और सकारात्मक वातावरण के माध्यम से सुशासन एवं कार्यकुशलता की नई मिसाल स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से अपेक्षा की कि वे सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए देवभूमि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के सरकार के "विकल्प रहित संकल्प" को सिद्धि तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर शासन के वरिष्ठ अधिकारी, सचिवालय संघ के पदाधिकारी तथा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

हरिद्वार में 5211 किलो वजनी विश्व के विशाल पारद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा

हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित श्री साई शिव गंगा धाम में 5211 किलोग्राम वजनी विश्व के विशाल पारद शिवलिंग की तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा विधि श्रद्धा, वैदिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक वातावरण के बीच सम्पन्न हुई। आयोजन में देशभर से आए 2000 से अधिक श्रद्धालुओं, साधकों, संत-महात्माओं और विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह गुरु गोरक्षनाथ महाराज की परंपरा, गिरनार के पूज्य पीर योगी महंत सोमनाथ बापू के आशीर्वाद तथा पद्मभूषण डॉ. विजय भटकर के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। आयोजन का उद्देश्य विश्व शांति, मानव कल्याण और सकारात्मक ऊर्जा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना था।

दस वर्षों की साधना से तैयार हुआ पारद शिवलिंग : ध्यान गुरु रघुनाथ गुरुजी द्वारा लगभग दस वर्षों की साधना, अनुसंधान और पारद विज्ञान के अध्ययन के बाद इस विशाल पारद शिवलिंग का निर्माण किया गया। इसके निर्माण में पारा, चांदी, स्वर्ण (गोल्ड) तथा 108 प्रकार की जड़ी-बूटियों के अर्क का उपयोग किया गया है। रघुनाथ गुरुजी के अनुसार यह शिवलिंग केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ध्यान, सकारात्मक ऊर्जा और मानव चेतना के जागरण का माध्यम है। इससे पूर्व वे वर्ष 2019 में लगभग 10,000 लोगों की सहभागिता के साथ एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी कर चुके हैं।प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनेक प्रतिष्ठित संत, धर्माचार्य और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इनमें जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज, सुधांशु महाराज, स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज, स्वामी अवध शानंद गिरी महाराज, स्वामी रविन्द्र पुरी महाराज, दिनेश चंद्र, विश्व हिन्दू परिषद संरक्षक, साध्वी ऋतंभरा, आचार्य मनीष, सांसद राघव चड्ढा, नितिन गौतम- गंगा सभा के अध्यक्ष,राज्य मंत्री सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे।

आयोजन की सफलता में राजीव बंसल की महत्वपूर्ण भूमिका: इस विशाल आयोजन को सफल बनाने में उद्योगपति एवं समाजसेवी राजीव बंसल की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। आयोजन की व्यवस्थाओं और समन्वय में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। राजीव बंसल ने कहा, ष्मैं साईं बाबा का भक्त हूं। मुझे बाबा का आशीर्वाद मिला कि मैं इस दिव्य कार्य का हिस्सा बन सका। यह मेरे लिए सेवा और श्रद्धा का अवसर था। ईश्वर की कृपा से हम सभी मिलकर इस कार्य को पूर्ण कर पाए।ष् ध्यान गुरु रघुनाथ गुरुजी ने भी समारोह के समापन पर सभी श्रद्धालुओं, संतों, स्वयंसेवकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए विशेष रूप से राजीव बंसल के योगदान की सराहना की। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सफलता में राजीव बंसल, आदरणीय दादाश्री, मनोज तोषनीवाल परिवार, मनोज गोहद, आईजी तकवाले, ममता जिवाल, तरुण भंडारी, अमित अग्रवाल, रमेश सांवरथिया, डॉलरभाई कोटेचा, सुधीर अग्रवाल, राजू ओसवाल और जितेन्द्र राठी सहित अनेक श्रद्धालुओं एवं सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

समाजसेवा और दिव्यांग सशक्तिकरण से भी जुड़ा अभियान : आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ-साथ रघुनाथ गुरुजी दिव्यांग आत्मनिर्भरता, महिला किसान सशक्तिकरण, पर्यावरण जागरूकता और नवाचार आधारित सामाजिक अभियानों से भी जुड़े हुए हैं। दिव्यांग इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें दिव्यांग इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित अग्रवाल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समारोह के अंत में ध्यान से शांति, शांति से सद्भाव और सद्भाव से विश्व कल्याण का संदेश दिया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने इसे आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और मानव कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

11 सूत्रीय माँगों को लेकर सौंपा मेयर को ज्ञापन

देहरादून। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी युवा मोर्चा ने स्वछता कर्मचारियों की वेतन बढ़ोत्तरी, पदोन्नति, 2018 तक दस वर्ष सेवा कर चुके कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार स्थाई नियुक्ति देने सहित 11

सूत्रीय माँगों को लेकर मेयर सौरभ थपलियाल एवं नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा।

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव राजोरी के नेत्रत्व में मोर्चा के कई पदाधिकारी ने अपनी माँगों से संबंधित ज्ञापन में कहा कि 29/04/26 को नगर निगम बोर्ड बैठक में आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों का दैनिक वेतन 800 रुपए करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था लेकिन अबतक लागू नहीं किया गया, निगम में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने 715 कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा था उक्त प्रस्ताव पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उत्तराखंड शासन के 10 दिसंबर 2025 के शासनादेश में संविदा, दैनिक वेतन, तदर्थ, कार्य प्रभारित एवं अंशकालिक, रात्रि गैंग, नाला गैंग आदि कर्मचारियों को विनियमितिकरण 2025 के अंतर्गत स्थाई किया जाना था जो बहुर ही खेदजनक है। मोर्चा ने स्वछता कर्मचारियों को आवास एवं भूमि उपलब्ध कराने के साथ, निगम के सभी 100 वार्डों में सफाई पर्यवेक्षकों में महिला को नियुक्त करने, कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाने, स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारियों के लिए गोल्डन एवं आयुष्मान कार्ड शिविर लगाने की माँग की साथ ही राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष/राज्यमंत्री भगवत प्रसाद मकवाना की माँग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदित महर्षि वाल्मीकि चौक के शीघ्र निर्माण की माँग की। मेयर एवं नगर आयुक्त ने सभी माँगों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वसन दिया।

अदानी समूह द्वारा बनाया जा रहा सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक रोपवे

पीपीपी मॉडल पर विकसित की जा रही रोपवे परियोजना

देहरादून। अदानी समूह द्वारा बनाया जा रहा सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक का रोपवे भारत सरकार की ''पर्वतमाला परियोजना'' के तहत एक अत्यंत महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा है। यह परियोजना चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर विकसित की जा रही है।

लगभग 12.9 किलोमीटर लंबा यह रोपवे दुनिया के सबसे लंबे और सबसे ऊंचे रोपवे सिस्टम्स में से एक होगा। इसके चालू होने के बाद श्रद्धालुओं की 8 से 9 घंटे की कठिन और थका देने वाली पैदल यात्रा मात्र 36 मिनट में पूरी हो सकेगी। इस भव्य प्रोजेक्ट में कुल रुपये 4,081 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। इसमें 3एस (त्रि-केबल डिटैचेबल) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो खराब मौसम और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में स्थिरता और पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह भारत का पहला 3 ट्राइकेबल रोपवे होगा। यह सिस्टम प्रति दिशा में प्रति घंटे 1,800 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा, जिससे सालाना 20 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसके बाद अदानी समूह 29 वर्षों तक इसका संचालन और रखरखाव करेगा। यह प्रोजेक्ट न केवल केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए भी दर्शन को अत्यंत आसान कर देगा। इससे उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में अब रोपवे परिवहन व्यवस्था भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत बनकर उभर रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते पर्यटन दबाव, यातायात जाम, पर्यावरणीय चुनौतियों और तीर्थ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने रोपवे नेटवर्क के विस्तार का बड़ा खाका तैयार किया है। इसी दिशा में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से ''उत्तराखंड रोडवेज डेवलपमेंट लिमिटेड'' का गठन किया गया है, जो राज्य में रोपवे परियोजनाओं को विकसित करने का कार्य कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने 2 सितंबर 2025 को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में उत्तराखंड रोपवेज डेवलपमेंट लिमिटेड का गठन किया। इस कंपनी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत और राज्य सरकार की 51 प्रतिशत है।

इसका उद्देश्य राज्य में रोपवे परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करना और पर्यटन और परिवहन क्षेत्र में नई संभावनाएं तैयार करना है। उत्तराखंड में फिलहाल दो महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजनाएं निर्माण प्रक्रिया में सबसे आगे हैं। इनमें पहली है- सोनप्रयाग- गौरीकुंड- केदारनाथ रोपवे और दूसरी-गोविंदघाट-घांघरिया-हेमकुंड साहिब रोपवे।

श्रद्धालुओं की सहभागिता से 'कैरी मी बैक' अभियान बना जनआंदोलन

रुद्रप्रयाग। हिमालयी पर्यावरण के संरक्षण एवं श्री केदारनाथ धाम को स्वच्छ, सुंदर और कचरा-मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा संचालित 'कैरी मी बैक' अभियान को श्रद्धालुओं का व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है। नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयास फाउंडेशन एवं सुलभ इंटरनेशनल की संयुक्त पहल से संचालित इस अभिनव अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 2 टन कचरा श्रद्धालुओं एवं स्वयंसेवकों के सहयोग से धाम क्षेत्र से नीचे लाया जा चुका है, जो पर्यावरण संरक्षण एवं जनभागीदारी आधारित स्वच्छता प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। अभियान के तहत श्रद्धालुओं को अपने साथ लाए गए प्लास्टिक, पानी की खाली बोतलों, खाद्य सामग्री के रैपर तथा अन्य गैर-जैविक अपशिष्ट को धाम में न छोड़कर वापस नीचे लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यात्रा मार्ग एवं श्री केदारनाथ धाम में तैनात कार्मिकों तथा स्वयंसेवकों द्वारा लगातार जनजागरूकता अभियान चलाकर यात्रियों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ धाम की स्वच्छता एवं हिमालयी पारिस्थितिकी का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 'कैरी मी बैक' अभियान में श्रद्धालुओं की बढ़ती भागीदारी अत्यंत उत्साहजनक है तथा लगभग 2 टन कचरे को धाम से नीचे लाया जाना इस बात का प्रमाण है कि जनसहयोग से बड़े और सकारात्मक बदलाव संभव हैं। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम की स्वच्छता बनाए रखना केवल प्रशासन का दायित्व नहीं, बल्कि समाज की भी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 'कैरी मी बैक' अभियान ने लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ जनभागीदारी आधारित कचरा प्रबंधन का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है। जिला प्रशासन भविष्य में भी इस प्रकार की पर्यावरण हितैषी पहलों को निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा।नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयास फाउंडेशन एवं सुलभ इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों ने बताया कि आगामी दिनों में अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को इस अभियान से जोड़ने तथा धाम को पूर्णतः स्वच्छ एवं कचरा-मुक्त बनाए रखने के लिए व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे श्री केदारनाथ धाम की पवित्रता एवं हिमालय की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में सक्रिय भागीदार बनें तथा अपने साथ उत्पन्न होने वाले कचरे को वापस नीचे गौरीकुंड लाकर इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें।

जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं का लिया जायजा

रुद्रप्रयाग। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2025 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 6174/2023 में पारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के क्रम में नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग के रैंतोली स्थित मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) का निरीक्षण कर वहां संचालित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी हरेन्द्र चौहान ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि नगर पालिका परिषद द्वारा डोर-टू-डोर सोर्स सेग्रीगेशन के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक कूड़ा एकत्रित किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2025 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप एकत्रित कूड़े को अलग-अलग वाहनों के माध्यम से एमआरएफ तक पहुंचाया जाता है, जहां अजैविक कचरे की आइटमवार छंटाई कर बेलिंग मशीन के माध्यम से उसकी बेल तैयार कर पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के लिए विक्रय किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एमआरएफ परिसर में एक ट्रॉमल मशीन, एक बेलिंग मशीन तथा एक श्रेडर मशीन स्थापित है। वहीं जैविक कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए छः छाक्न्च पिट एवं एक ऑर्गेनिक वेस्ट कम्पोस्टिंग मशीन संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त घरेलू बायो-मेडिकल अपशिष्ट, जैसे डायपर एवं सैनिटरी पैड आदि के सुरक्षित निस्तारण के लिए 100 किलोग्राम क्षमता की एक इंसिनरेटर मशीन भी स्थापित की गई है। अधिशासी अधिकारी ने जानकारी दी कि नगर क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग 4.5 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का संग्रहण कर उसका नियमित रूप से उसी दिन वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही एमआरएफ को और अधिक विस्तारित एवं आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया भी संचालित की जा रही है।

निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने नगर पालिका परिषद द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2025 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए नगर क्षेत्र में स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। इस अवसर पर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग संतोष रावत, उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग सोहन सिंह सैनी, नायब अर्जुन सिंह पंवार, राजस्व उपनिरीक्षक प्रियंका, प्रभारी सफाई निरीक्षक चन्द्रशेखर चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री ने किया उपाध्यक्ष के कार्यालय का उद्घाटन

देहरादून । प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष शमशेर सिंह बिष्ट के कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण, उत्थान एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कार्यालय पूर्व सैनिकों और परिषद के मध्य समन्वय स्थापित करने तथा जनसेवा के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने का केंद्र बनेगा। मंत्री जोशी ने सैनिक कल्याण परिषद में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में परिषद समाज के हितों के लिए प्रभावी कार्य करेगी तथा राज्य के विकास में सैनिक समाज की सहभागिता को और सुदृढ़ करेगी। इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, दायित्वधारी ज्योति कोटिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

ममता के आंसूओं का मर्म

राजनीति में नेता कब चौला बदल ले, पता नहीं चलता। कांग्रेस को आंखे दिखाने वाली पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सोनिया गांधी से मिली उनकी आंखों में आंसू भर आए।

यह वाक्या बताता है कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं है। दोस्त कब दुश्मन बन जाएं और दुश्मन कब दोस्त, इसका राजनीतिक इतिहास पुराना है। इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक के दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की भावुक मुलाकात ने कांग्रेस-टीएमसी के 30 साल पुराने उतार-चढ़ाव वाले संबंधों और बंगाल चुनाव के बाद आयी दरारों को फिर से चर्चा में ला दिया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी अपनी पार्टी में टूट के बीच जब बैठक में पहुंचीं, तो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। बंद कमरे में अपनी पुरानी सहेली और राजनीतिक साथी को सामने देख ममता बनर्जी के आंसू छलक पड़े।ममता के ये आंसू दरअसल कांग्रेस के साथ किए गए अपने खराब पुराने बर्ताव या कांग्रेस से अलग होने की गलती के एहसास की वजह से नहीं आए, बल्कि भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव जीत कर सारा दंभ हवा होने से गई सत्ता गंवाने और अपने सांसदों के टूटने की वजह से आएं। दरअसल पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने और पार्टी के सांसदों के विद्रोह से ममता के राजनीतिक अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। जिसकी ममता बनर्जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ममता को सोनिया गांधी से मिली 'जादू की झप्पी' सिर्फ व्यक्तिगत ढाढ़स नहीं थी। यह कांग्रेस और टीएमसी के बीच पिछले 3 दशकों से चले आ रहे उतार-चढ़ाव, पुरानी राजनीतिक दरारों और बंगाल में एक-दूसरे के वजूद को मिटाने की खूनी क्रोनोलॉजी का अंतिम और सबसे असहाय पड़ाव था। 1997-98 में ममता बनर्जी ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व (सोनिया गांधी के उभार के समय) पर वामपंथियों (वाममोर्चा) के खिलाफ ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था। ममता ने अलग तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। अगले दो दशक में ममता बनर्जी ने वामपंथ के साथ-साथ कांग्रेस को भी बंगाल में शून्य कर दिया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस को महज दो सीटों पर ही लोकसभा चुनाव लड़ने की पेशकस की थी, मगर कांग्रेस टीएमसी से 10-12 सीटों की डिमांड कर रही थी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की 10-12 लोकसभा सीटों की मांग को 'अनुचित' बताया था और पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर चर्चा में देरी के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। ममता ने 'एकला चलो' की नीति अपनाते हुए बहरमपुर में यूसुफ पठान को उतारकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। इससे दिल्ली का कांग्रेस नेतृत्व अंदर से बेहद आहत था। कांग्रेस पार्टी के पारंपरिक गढ़ों (मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर) को भी पूरी तरह से ममता बनर्जी ने निगल लिया। अधीर रंजन चौधरी जैसे कद्दावर नेताओं को साइडलाइन कर उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक पर अपना एकछत्र राज स्थापित कर लिया था।

चिन्ताजनक : महंगी होती दवाइयां, महंगा होता इलाज

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने के स्वप्न के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना बार-बार दोहराई जा रही है। बड़े-बड़े बुनियादी ढांचे,

डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां और आर्थिक विकास के दावों के बीच एक प्रश्न बार-बार सामने खड़ा हो जाता है-क्या ऐसा भारत वास्तव में विकसित कहलाएगा, जहां एक सामान्य नागरिक बीमारी के कारण कर्ज में डूबने को विवश हो जाए? जहां इलाज और दवाइयों की बढ़ती कीमतें जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय करने लगें? जहां स्वास्थ्य सेवा अधिकार नहीं, बल्कि आर्थिक सामर्थ्य का विषय बन जाए? ऐसे समय में जब महंगाई पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ रही है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एन.पी.पी.ए.) द्वारा कुछ जीवनरक्षक दवाओं और टीकों की कीमतों में भारी वृद्धि की अनुमति देना गंभीर चिंता का विषय है। कैंसर की कुछ दवाओं, एंटी-टेटनस सीरम और बच्चों के आवश्यक टीकों की कीमतों में लगभग पचास प्रतिशत तक वृद्धि की स्वीकृति ने लाखों परिवारों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। यह निर्णय केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना और जनकल्याणकारी शासन की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है।भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में लोग आज भी अपने इलाज का खर्च अपनी जेब से वहन करते हैं। बीमारी केवल स्वास्थ्य संकट नहीं रह जाती, वह आर्थिक संकट में भी बदल जाती है। एक समय था जब कहा जाता था कि व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के कारण कर्ज में डूबता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि किसी गंभीर बीमारी का इलाज पूरा परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है। कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग या अन्य जटिल बीमारियों का उपचार लाखों रुपये की मांग करता है। ऐसे में यदि जीवनरक्षक दवाइयों की कीमतें भी लगातार बढ़ती रहें तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा लगभग असंभव हो जाएगी। एन.पी.पी.ए. ने दवाओं की कीमत बढ़ाने के पीछे उत्पादन लागत में वृद्धि और बाजार में संभावित कमी का तर्क दिया है। उनका कहना है कि यदि दवा कंपनियां लागत भी नहीं निकाल पाएंगी तो वे उत्पादन बंद कर सकती हैं, जिससे मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। यह तर्क अपनी जगह सही हो सकता है। किसी भी उद्योग को जीवित रहने के लिए उचित लाभ आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जीवनरक्षक दवाओं को सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की तरह देखा जा सकता है? क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ कमाने की सीमा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया जाना चाहिए?

स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। दुर्भाग्य से भारत में इन दोनों क्षेत्रों में व्यवसायीकरण का प्रभाव लगातार बढ़ता गया है। निजी अस्पतालों की बढ़ती फीस, महंगे परीक्षण, अनावश्यक जांचें, चिकित्सा उपकरणों का भारी खर्च और अब दवाइयों की बढ़ती कीमतें मिलकर आम नागरिक को असहाय बना रही हैं। चिकित्सा सेवा धीरे-धीरे सेवा के बजाय उद्योग में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र कम और कॉरपोरेट प्रतिष्ठान अधिक प्रतीत होने लगे हैं। रोगी अब मरीज नहीं, बल्कि ग्राहक की तरह देखा जाने लगा है। यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सामाजिक विभाजन को भी गहरा करती है। आज भी देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यत: उन्हीं लोगों को उपलब्ध हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारों, सीमित संसाधनों और अपर्याप्त सुविधाओं के भरोसे है। अमीर व्यक्ति अत्याधुनिक अस्पतालों और महंगे उपचारों का लाभ उठा सकता है। क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या यही वह भारत है जिसकी कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक जनहितकारी योजनाएं लागू हुई हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना ने लाखों लोगों को राहत भी प्रदान की है। जन औषधि केंद्रों की स्थापना ने सस्ती दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में व्याप्त व्यापक विसंगतियां अभी भी बनी हुई हैं। यदि दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहें और निजी स्वास्थ्य सेवाएं अनियंत्रित होती जाएं, तो इन योजनाओं का प्रभाव सीमित हो जाएगा। वास्तविक चुनौती यह है कि स्वास्थ्य को बाजार की शक्तियों के हवाले छोड़ने के बजाय उसे जनकल्याण के केंद्र में रखा जाए। सरकार का दायित्व केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों पर विशेष नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दवा खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आवश्यक दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विशेष सहायता और सब्सिडी भी दे सकती है, ताकि लागत बढ़ने का पूरा बोझ मरीजों पर न पड़े।

इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा और व्यापक होना चाहिए। अनेक गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवार ऐसे हैं जो किसी भी बीमा सुरक्षा से वंचित हैं। गंभीर बीमारी की स्थिति में वे अपनी जीवनभर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। स्वास्थ्य बीमा केवल अस्पताल में भर्ती होने तक सीमित न रहे, बल्कि आवश्यक दवाओं और दीर्घकालिक उपचार को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सरकार समय-समय पर दवा कंपनियों की लागत संरचना और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्र समीक्षा कराए। यदि वास्तव में लागत बढ़ी है तो उसका प्रमाण सार्वजनिक होना चाहिए। पारदर्शिता से जनता का विश्वास भी बढ़ेगा और अनावश्यक मूल्यवृद्धि पर भी रोक लगेगी। स्वास्थ्य नीति का मूल उद्देश्य कंपनियों के लाभ और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए।

वर्ष 2047 का विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, तेज रफ्तार सड़कों और बढ़ती जीडीपी से नहीं बनेगा। उसका वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि वहां का सबसे गरीब नागरिक कितना सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ है। यदि एक किसान, मजदूर, कर्मचारी या निम्न आय वर्ग का व्यक्ति बीमारी के समय सम्मानपूर्वक इलाज प्राप्त नहीं कर सकता, तो विकास के दावे अधूरे रह जाएंगे। आज आवश्यकता केवल दवाइयों की कीमतों पर बहस करने की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की समग्र समीक्षा करने की है। यह स्वीकार करना होगा कि स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं, बल्कि मौलिक मानवीय अधिकार है। जिस राष्ट्र में नागरिकों को स्वस्थ जीवन का अवसर नहीं मिलता, वहां विकास की चमक भी फीकी पड़ जाती है। समय आ गया है कि सरकार, नीति-निर्माता, चिकित्सा जगत और समाज मिलकर यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवा लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का सशक्त उपकरण बने। अन्यथा विकसित भारत का सपना केवल आंकड़ों में चमकेगा, जबकि आम आदमी बीमारी, कर्ज और असहायता के अंधकार में संघर्ष करता रहेगा। स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ते भारत के सामने यही सबसे बड़ी नैतिक और मानवीय चुनौती है, जिसका समाधान आज ही तलाशना होगा।

प्रमुख सचिव ने की आपदा तैयारियों एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा

देहरादून। प्रमुख सचिव एवं जनपद प्रभारी, देहरादून डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में मानसून पूर्व तैयारियों एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के नेतृत्व में संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा मानसून तैयारी के दृष्टिगत जनपद में संचालित विभिन्न कार्यों, संवेदनशील स्थलों पर की गई व्यवस्थाओं, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में चल रहे शमन कार्यों तथा गत वर्ष की आपदाओं एवं जलभराव से प्राप्त अनुभवों के आधार पर की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।

बैठक में सौंग नदी परियोजना, नंदा की चौकी क्षेत्र में चल रहे सुरक्षा कार्यों, नदी सफाई कार्यों तथा अन्य बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने मानसून आरंभ होने से पूर्व सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही खनन गतिविधियों से संबंधित आवश्यक कार्यवाहियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने को कहा।

मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु जनपद में उपलब्ध 39 डी-वॉटरिंग पंपों की तैनाती योजना की समीक्षा की गई।

गत वर्ष जलभराव एवं जनहानि से प्रभावित स्थलों का पुन: आकलन कर संवेदनशील क्षेत्रों में अग्रिम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आईएसबीटी क्षेत्र में जलनिकासी संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु एमडीडीए, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, सिंचाई विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम गठित कर समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अतिरिक्त जनपद के 12 प्रमुख नालों की सफाई एवं सुधार कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में अल्प अवधि में होने वाली अत्यधिक वर्षा (शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल) वाले क्षेत्रों का डेटा आधारित विश्लेषण करने तथा संभावित जलभराव स्थलों की अग्रिम पहचान सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। आठ संवेदनशील नदी एवं नाला क्षेत्रों में चल रहे शमन कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को नियमित मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

भूस्खलन एवं भू-संवेदनशील क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए जनपद में चिन्हित 12 लैंडस्लाइड जोन तथा क्रॉनिक स्लिप जोन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। किमाड़ी सहित संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी समाधान विकसित करने तथा जोखिम कम करने हेतु दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्लाउड बर्स्ट की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में निगरानी एवं पूर्व चेतावनी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।

बैठक में जोखिमयुक्त एवं आपदा संभावित विद्यालयों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को ऐसे विद्यालयों की पहचान कर शेष मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार अस्थायी एवं स्थायी दोनों प्रकार के समाधान विकसित करने को कहा गया। इसी प्रकार उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निवासरत गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित आवागमन तथा अन्य आवश्यक सहायता पूर्व से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा के दौरान डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु व्यापक अभियान चलाने, नियमित फॉगिंग, जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित करने तथा जलभराव वाले स्थलों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि लीकेज मैपिंग के दौरान 18 स्थानों पर रिसाव चिन्हित किए गए हैं, जिनके निराकरण की कार्यवाही प्रगति पर है। बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में 169 नाले हैं जिनमें से 153 पर सफाई कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष पर सफाई कार्य गतिमान है। मानसून अवधि के दौरान 89 स्कूलों का चिन्हिकरण किया गया है, जिनमें बरसात के समय नदी-नाले पड़ते है, तथा 73 गांव ऐसे है, जहां पर समुचित कनैक्टीविटी नही है, ऐसे गांव की गर्भवती महिलाओं को पहले ही नजदीकी चिकित्सालय भर्ती कराने की व्यवस्था की गई है जहां गर्भवती महिला एवं तीमारदार के भोजन आदि व्यवस्था विभाग की रहेगी। प्रमुख सचिव ने संभावित वृक्ष गिरने की घटनाओं की रोकथाम के लिए चिन्हित स्थलों पर समयबद्ध कार्रवाई करने तथा अन्य जर्जर एवं जोखिमयुक्त वृक्षों की भी पहचान कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त रैन बसेरों, राहत शिविरों तथा अन्य आपदा राहत व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से तैयार रखने को कहा गया। प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि मानसून अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में त्वरित एवं समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देशित किया कि संवेदनशील स्थलों की नियमित निगरानी, पूर्व चेतावनी तंत्र की प्रभावी कार्यप्रणाली तथा राहत एवं बचाव संसाधनों की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित की जाए, जिससे जनहानि एवं संपत्ति की क्षति को न्यूनतम किया जा सके। उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वार रूम एवं नियंत्रण कक्ष को 24x7 सक्रिय रखने तथा सभी विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए। बैठक में गत वर्ष की आपदाओं से हुई क्षति, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, आपदा उपरांत क्षति आकलन रिपोर्टों तथा कृषि क्षेत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि बीज एवं अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता तथा वितरण में किसी प्रकार की देरी न होने दी जाए।

बैठक उपरांत प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम ने जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान एवं संबंधित अधिकारियों के साथ कालीगाड़ एवं माझाड़ा क्षेत्र सहित आपदा प्रभावित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर क्षेत्र में पुनर्वास कार्य, नदी चौनलाईजेशन कार्य, पुनर्वास व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान, मुख्य नगर आयुक्त आलोक कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार, अपर जिलाधिकारी वि/रा के.के मिश्रा, प्रभागीय वनाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ मनोज कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, जिला पूर्ति अधिकारी के.के अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान नमित रमोला सहित अधिशासी अभियंता लोनिवि, सिचांई, पेयजल, विद्युत आदि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

शिवसेना राज्य प्रमुख गौरव कुमार का हुआ सम्मान

देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए शिवसेना के राज्य प्रमुख गौरव कुमार को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अजय आर्य, दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आर.एस. बिष्ट तथा राजकीय दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने गौरव कुमार को सम्मान-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके सामाजिक योगदान की सराहना की।

इस अवसर पर गौरव कुमार ने कहा कि रक्तदान एक महादान है, जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन देने का माध्यम बनता है। उन्होंने लोगों से नियमित एवं स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय-समय पर रक्तदान कर मानवता की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्त की आवश्यकता कभी भी किसी के सामने आ सकती है, इसलिए समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में मनोज सरीन एवं मनमोहन साहनी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान रक्तदाताओं के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया गया।

जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को लेकर आयोजित होंगे शिविर

रुद्रप्रयाग। केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी और विकासपरक योजनाओं को आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से जनपद रुद्रप्रयाग में आगामी 20 जून तक विभिन्न स्थानों पर जनकल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों की प्रदर्शनी के साथ-साथ पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण एवं समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 जून (शुक्रवार) को नगर पंचायत गुप्तकाशी एवं जिला पंचायत कार्यालय रुद्रप्रयाग में जन कल्याणकारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं 20 जून को नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग तथा तहसील सभागार बसुकेदार में भी शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शिविरों के दौरान जनपद के सार्वजनिक स्थलों पर केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही ऑन-द-स्पॉट चित्रकला प्रतियोगिता, वॉक्स पॉप वीडियो रिकॉर्डिंग, लाभार्थियों के अनुभव साझा करने जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर, पीएम स्वनिधि, लखपति दीदी सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा। मुख्य विकास अधिकारी ने उक्त शिविरों के सफल संपादन हेतु अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अधिक से अधिक लाभार्थियों को शिविरों तक लाकर योजनाओं से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं।

मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता की जांच

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण -ट्राई ने गोरखपुर शहर और आसपास के इलाकों गोरखनाथ, झुंगिया, रतनपुर, पिपराइच, रामपुर बुजुर्ग, भटहट, मंगलपुर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गोरखपुर, गोविंदपुर, कालेसर, बेलघाट, माडापार, गोरखपुर हवाई अड्डा, तारामंडल, रामजानकी नगर और शाहपुर में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया।

ट्राई ने मई 2026 के दौरान दूरसंचार विभाग के उत्तर प्रदेश (पूर्व) लाइसेंस सेवा क्षेत्र के तहत गोरखपुर शहर और लखनऊ से गोरखपुर रेल मार्ग पर आयोजित स्वतंत्र टेस्ट ड्राइव के निष्कर्ष आम दूरसंचार उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए जारी किए हैं। इस टेस्ट ड्राइव का उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल नेटवर्क वॉयस और डेटा सेवा की वास्तविक समय में गुणवत्ता जांच और सत्यापन करना है। ट्राई, स्वतंत्र टेस्ट ड्राइव में, कवरेज, कॉल ड्रॉप रेट (कॉल करने वाले और कॉल रिसीव करने वाले दोनों में से कोई भी कॉल काट नहीं पाता और फोन अचानक अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है), कॉल सेटअप की सफलता दर, डेटा डाउनलोड और अपलोड थ्रूपुट (डेटा अपलोड और डाउनलोड होने की वास्तविक गति) आदि प्रमुख सेवा गुणवत्ता मानदंड़ों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करता है, जिन्हें बाद में उपभोक्ताओं को सूचित करने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवाओं में सुधार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है। इन आंतरिक डेटा जांच उपाय को शहरों, हॉटस्पॉट, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों आदि विभिन्न उपयोग परिवेशों में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मोबाइल नेटवर्क प्रदर्शन मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार के ड्राइव टेस्टिंग में, 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क पर सभी सेवा प्रदाताओं के सिम कार्ड का उपयोग कर लाइव डेटा और वॉयस सेशन आयोजित किए जाते हैं। इसमें उन्नत टेस्ट हैंडसेट का उपयोग किया जाता है, और उन्नत सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग कर रियल-टाइम निगरानी और विश्लेषण किया जाता है। ट्राई ने अपनी निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा 4 मई 2026 से 8 मई 2026 के बीच उत्तर प्रदेश पूर्व लाइसेंस सेवा क्षेत्र में गोरखपुर शहर और लखनऊ से गोरखपुर रेल मार्ग पर सिटी ड्राइव (342.1 किलोमीटर), हॉटस्पॉट लोकेशन (11), वॉक टेस्ट (3.7 किलोमीटर) और रेलवे (296.3 किलोमीटर) सहित ड्राइव टेस्ट आयोजित किए। ये परीक्षण ट्राई के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की देखरेख में किए गए। ड्राइव टेस्ट रिपोर्ट में प्रस्तुत अवलोकन ड्राइव टेस्ट के दिन/समय पर परीक्षण क्षेत्र/मार्ग पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन दर्शाते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने की समग्र कृषि क्षेत्र की समीक्षा

अल नीनो से निपटने की रणनीति, हर हफ्ते होगी बैठक

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन, में उच्चस्तरीय साप्ताहिक कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 के लिए देशभर की तैयारियों की गहन समीक्षा की। साथ ही, संभावित अल नीनो परिस्थितियों के बीच उन्होंने कपास का उत्पादन बढ़ाने, दलहन में आत्मनिर्भरता और कम बारिश वाले जिलों के लिए अग्रिम कंटिंजेंसी प्लान पर विशेष जोर देते हुए साफ संदेश दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में किसान हितों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठक में अल नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ निर्देश दिया कि जिन जिलों में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है, वहां पहले से पूरी तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान कर राज्य सरकारों के साथ मिलकर फसलवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार किए जाएं, ताकि किसी भी मौसमीय चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि पानी के संरक्षण, नमी प्रबंध न, इंटरक्रॉपिंग और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान देते हुए, हर जोखिम वाले जिले के लिए अलग और व्यावहारिक रणनीति बनाई जाए। श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी निर्देश दिए कि जिन 9ख्र10 राज्यों में अल नीनो का प्रभाव अपेक्षाकृत अधि क पड़ सकता है, वहां के चिन्हित जिलों के जिला अधिकारियों, कृषि विभाग, केवीके और अन्य विस्तार तंत्र के साथ समन्वित बैठकें आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में जिला स्तर पर पूरी स्थिति स्पष्ट कर किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि हर किसान को यह पता रहे कि उसके क्षेत्र के लिए कौन-सी सावधानियां और कौन-से फसल विकल्प अधिक सुरक्षित हैं। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के बजाय, वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर शांत, भरोसेमंद और समाधान-उन्मुख संदेश किसानों तक पहुंचे, यही सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में खरीफ 2026 के लिए फसलवार लक्ष्य, बुवाई की प्रगति और राज्यवार तैयारियों की समीक्षा करते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। श्री शिवराज सिंह चौहान ने वैज्ञानिक तरीकों, सही किस्मों के चयन, अंतरफसली खेती, मल्चिंग और नमी संरक्षण जैसे उपायों को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने पर जोर दिया, ताकि कपास की उत्पादकता और आय दोनों में सुध ार हो। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि अरहर, उड़द, मूंग जैसी दालों में देश अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बने और आयात पर निर्भरता कम हो। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर फसल चक्र, क्षेत्र विस्तार, बेहतर बीज उपलब्धता और तकनीकी मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसान सुरक्षित आय के साथ दलहन उत्पादन बढ़ा सकें।

समीक्षा के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता, बाजार में मंडी भाव, जलाशयों व जल भंडारण की स्थिति और राज्यवार स्टॉक की जानकारी भी प्रस्तुत की गई। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक उपलब्धता है और जैसे-जैसे मानसून की रफ्तार बढ़ेगी, राज्यों और जिलों तक आपूर्ति को और चुस्त-दुरुस्त रखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देने के साथ ही इस पर भी जोर दिया कि जहां कहीं भी सूक्ष्म स्तर पर कमी की आशंका दिखे, वहां अग्रिम रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसान को किसी तरह की दिक्कत न हो। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों, केवीके और राज्यों के कृषि विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी ज्ञान तभी सार्थक है, जब वह समय पर खेत तक पहुंचे और किसान उसे आसानी से अपनाकर लाभ उठा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सतत संवाद, नियमित समीक्षा और जमीन से जुड़े फीडबैक के आधार पर ही खरीफ 2026 को सफल और सुरक्षित बनाया जा सकता है।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण खत्री ने दी बमोथ में ग्रामीणों के प्रस्तावों को मंजूरी

गौचर /चमोली । विकासखंड पोखरी के गंगनानी क्षेत्र के गांवों का भ्रमण करते हुऐ जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह खत्री ने रानो, बमोथ व नाग काण्डा, तोली गेलुंग आदि में ग्रामीणों की समस्याऐं सुनते हुऐ उनके निराकरण किऐ जाने का आश्वासन दिया गया। ग्राम पंचायत बमोथ के पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ मिलन गोष्ठी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह खत्री ने बुजुर्गो तथा महिलाओं का हाल चाल पूछा और कहा कि किसी को कोई भी समस्या है तो उसका निवारण करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उनके समक्ष नाली निर्माण, मार्ग निर्माण, मरम्मत तथा रास्तों पर टाइल्स लगाने के अलावा गांव के चार तोकों में महिला मंगल दलों को शादी विवाह हेतु टेन्ट सामग्री उपलब्ध कराऐ जाने बाबत प्रस्ताव रखे गये। उपाध्यक्ष खत्री जी ने ग्रामीणों की समस्याऐं सुनते हुऐ उनके द्वारा ग्राम विकास के संवंध में रखे गये सभी प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी गई तथा वर्तमान समय में अपने द्वारा स्वीकृत किऐ गये निर्माण कार्यों पर ग्रामीणों से चर्चा की गई और हो रहे कार्यों पर निगरानी रखने को कहा गया। उन्होंने कहा कि गांव के लगभग सभी मुख्य रास्तों पर टाइल्स लगवाया जायेगा ताकि आने जाने में किसी तरह की समस्याऐं न हो। ग्रामीणों ने उनके द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों पर खुशी जताते हुऐ उनके प्रति ध न्यवाद ज्ञापित किया है। इस अवसर पर महिला मंगल दल अध्यक्ष दीपा नेगी सहित भारी संख्या में महिलाएं तथा प्रधान के प्रतिनिधि प्रीतम ठाकुर, चक्रध र प्रसाद चमोला, बृजमोहन भट्ट, पूर्व प्रधान ललिता प्रसाद लखेड़ा, चंडी प्रसाद पन्त, राजेश्वर प्रसाद सिलोड़ा आदि मौजूद रहे।

जंगल की आग बुझाने गये वनकर्मी की आग की चपेट में आने से मौत

पुरोला /उत्तरकाशी। टॉन्स वन प्रभाग पुरोला के जंगल में लगी आग को बुझाने गये एक वनकर्मी की आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है!वनकर्मी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया हैं!

प्राप्त जानकारी के टॉन्स वन प्रभाग पुरोला के अंतर्गत वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर कार्यरत सोहन;सिंह;रावत , जो ठडूग बीट में तैनात थे, बुधवार रात जंगल में लगी आग को बुझाने के दौरान कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। रेंज अधिकारी पुरोला रेंज श्रीमती अमिता थपलियाल ने बताया की मृतक वनकर्मी तीन अन्य कर्मियों के साथ वनाग्नि को बुझाने के लिए गये थे, लेकिन देर रात को लगभग साढ़े आठ बजे के करीब उक्त वनकर्मी आग बुझाते समय वनाग्नि की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई!रेंज अधिकारी ने बताया कि उक्त वनकर्मी ने कुछ समय पूर्व ही पुरोला रेंज में ट्रांसफर होकर आया था!वनकर्मी की दर्दनाक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है!वनकर्मी की मौत पर क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल, पूर्व विधायक मालचंद, ब्लॉक प्रमुख सहित जनप्रतिनिधि, ग्रामीणों ने शोक ब्यक्त किया है!

सुरक्षात्मक कार्यों को गति देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद

चम्पावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों एवं जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में जनपद चम्पावत के समस्त सड़क मार्गों को सुचारू रखने तथा मानसून अवधि के दृष्टिगत सुरक्षात्मक कार्यों को गति देने हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जनपद चम्पावत के समस्त मुख्य एवं ग्रामीण मार्ग पूर्णतः सुचारू है।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में किसी भी संभावित आपदा अथवा मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति से निपटने के लिए सभी सड़क निर्माण एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिनके द्वारा प्रभावित मार्गों को त्वरित गति से सुचारू करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। आपदा पूर्व तैयारियों के अंतर्गत सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा विभिन्न मार्गों पर मलबे की सफाई, नालियों व कल्वर्ट (पुलिया) की सुचारू निकासी तथा सड़कों के किनारे उगी झाड़ियों के कटान का कार्य युद्धस्तर पर संचालित किया जा रहा है, ताकि यातायात पूर्णतः सुरक्षित और निर्बाध बना रहे।

बिग बॉस 20 | 'पुराने बनाम नए चेहरे' की थीम के साथ मचेगा बवाल, उर्फी जावेद से लेकर फैसल शेख तक ये सितारे आ सकते हैं नजर

भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़े और सबसे विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के फैंस के लिए बेहद रोमांचक खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान एक बार फिर बिग बॉस सीजन 20 (Bigg Boss 20) के साथ होस्ट की कुर्सी पर धमाकेदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक इस सीजन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक शो की प्रीमियर डेट, संभावित कंटेस्टेंट्स और इस बार की अनोखी थीम को लेकर बड़ी जानकारियां लीक हो गई हैं। आइए जानते हैं बिग बॉस 20 से जुड़ी अब तक की हर बड़ी अपडेट:-

कब शुरू होगा बिग बॉस 20? (प्रीमियर डेट)

वैराइटी इंडिया (Variety India) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस खास 20वें सीजन की तैयारियां पर्दे के पीछे बेहद तेजी से चल रही हैं। खबरों की मानें तो शो की शूटिंग और इसका ग्रैंड प्रीमियर 21 सितंबर 2026 से शुरू हो सकता है। फैंस लंबे समय से भाईजान के इस शो का इंतजार कर रहे हैं और सितंबर के तीसरे हफ्ते में यह इंतजार खत्म होने की पूरी उम्मीद है।

इस बार की लीक थीम: पुराने बनाम नए चेहरे

बिग बॉस का हर सीजन अपनी अनोखी थीम के लिए जाना जाता है, और खबरों के अनुसार इस 20वें सीजन को महा-रोमांचक बनाने के लिए मेकर्स एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं।

क्या है अफवाह?

इस बार की थीम पुराने बनाम नए चेहरे (Old vs Fresh Faces) होने की चर्चा है। इसके तहत घर में कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज एंट्री लेंगे जो पहली बार इस शो का हिस्सा बनेंगे, वहीं उन्हें टक्कर देने के लिए बिग बॉस के इतिहास के कुछ सबसे लोकप्रिय और विवादित पूर्व कंटेस्टेंट्स (Ex-Contestants) की भी दोबारा एंट्री कराई जा सकती है।

मेकर्स का मुख्य फोकस इस बार युवा और ओटीटी (OTT) दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने का है, इसलिए लिस्ट में कई सोशल मीडिया स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स के नामों पर विचार किया जा रहा है।

संभावित कंटेस्टेंट्स की लिस्ट (Probable Contestants List)

इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस सीजन के पहले संभावित कंटेस्टेंट के रूप में मशहूर रैपर सैंटी शर्मा का नाम सबसे पहले सामने आया था। इसके बाद से ही संभावित चेहरों की एक लंबी लिस्ट वायरल हो रही है, जिनसे मेकर्स की बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है:

सोशल मीडिया स्टार्स और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स

इस बार मेकर्स का मुख्य फोकस ओटीटी (OTT) और युवा दर्शकों को आकर्षित करने पर है, इसलिए कई बड़े इंटरनेट चेहरों को अप्रोच किया गया है:

फैसल शेख (मिस्टर फैसू): सोशल मीडिया की दुनिया का एक बेहद लोकप्रिय नाम। फैसू की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। वे इससे पहले श्खतरों के खिलाड़ीश और श्झलक दिखला जाश जैसे रियलिटी शोज में अपने हुनर और सादगी से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। बिग बॉस के घर में उनकी एंट्री शो की टीआरपी को आसमान पर ले जा सकती है।

अंजलि अरोड़ा: कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा पहले भी कंगना रनौत के रियलिटी शो श्लॉक अपश में नजर आ चुकी हैं, जहाँ वे फाइनलिस्ट रही थीं। अपनी बोल्ड पर्सनालिटी और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली अंजलि घर के अंदर काफी ड्रामा और मनोरंजन ला सकती हैं।

उर्फी जावेद: अपने अतरंगी और अनोखे फैशन सेंस से लगातार सुर्खियों में रहने वाली उर्फी जावेद किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। वे बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन में दिख चुकी हैं, लेकिन मुख्य शो (Main Show) में उनका आना इस सीजन के एंटरटेनमेंट और विवादों के ग्राफ को काफी ऊपर बढ़ा सकता है।

काजल अग्रवाल बर्थडे: जर्नलिस्ट बनने आई थीं, 'सिंघम' गर्ल ऐसे बनीं बॉलीवुड-साउथ की क्वीन

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में धूम मचा चुकी अभिनेत्री काजल अग्रवाल आज यानी की 19 जून को अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं। काजल अग्रवाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आज तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काजल अग्रवाल सबसे अधिक डिमांड की जाने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं। तो आइए जानते हैं उनके जन्मदिन के मौके पर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में...

जन्म और परिवार

एक पंजाबी परिवार में 19 जून 1985 को काजल अग्रवाल का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के सेंट एनी हाई स्कूल से पूरी की है। फिर काजल ने केसी कॉलेज मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन मास मीडिया स्ट्रीम में पूरा किया। काजल अग्रवाल ने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। वह एक टीवी जर्नलिस्ट बनना चाहती थीं। लेकिन किस्मत ने उनको एक्ट्रेस बना दिया था। फिल्मों में आने से पहले काजल एमबीए की पढ़ाई करने का विचार बना रही थीं।

फिल्मी सफर

काजल अग्रवाल ने फिल्म श्लक्ष्मी कल्याणमश में कल्याण राम के अपोजिट तेलुगू सिनेमा जगत में डेब्यू किया था। एक्ट्रेस को पहली कमर्शियल सफलता तेलुगु मूवी श्चंदामामाश से मिली थी। वहीं साल 2009 में आई फिल्म श्मगधीराश ने काजल को तेलुगु सिनेमा का स्टार बना दिया। इसके बाद काजल के अभिनय की गाड़ी दौड़ पड़ी। फिल्म श्मगधीराश में काजल के अपोजिट अभिनेता रामचरण तेजा थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाई की है। काजल बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस के फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई थीं।

बॉलीवुड डेब्यू

वहीं काजल अग्रवाल ने बॉलीवुड में डायरेक्टर रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी श्सिंघमश से डेब्यू किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में काजल ने अभिनेता अजय देवगन के साथ काम किया था। इससे पहले साल 2004 में आई फिल्म श्क्यों! हो गया नश से काजल ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम किया था। इस फिल्म में काजल अग्रवाल ने ऐश्वर्या की बहन का रोल किया था।

लॉकडाउन के दौरान हुआ प्यार

काजल की गौतम से मुलाकात सालों पहले एक कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी। फर्स्ट मीटिंग के बाद काजल और गौतम के बीच दोस्ती हुई। दोनों करीब 7 साल तक दोस्त रहे और फिर दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। शादी करने से पहले करीब 3 सालों तक दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया। लेकिन जब लॉकडाउन में कई हफ्तों तक दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी, तो दोनों को एहसास हुआ कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद काजल और गौतम ने शादी कर ली।

रेड रोड पर ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए कोलकाता पूरी तरह तैयार

नई दिल्ली। कोलकाता 21 जून को मशहूर रेड रोड पर 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) के राष्ट्रीय समारोह की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्कॉमन योग प्रोटोकॉलश में देश का नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह से पहले, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी और आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज नबन्ना सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व, व्यापक स्वरूप और तैयारियों पर प्रकाश डाला।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी और आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने पश्चिम बंगाल सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री अशोक कुमार की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में बारह विशेष डाक टिकट जारी किए।

प्रेस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के राष्ट्रीय समारोह की मेजबानी करना पश्चिम बंगाल के लिए अत्यंत गौरव की बात है। उन्होंने कोलकाता को एक समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत वाला शहर बताया, जो स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण के मूल्यों को निरंतर बनाए रखता है। मुख्यमंत्री ने योग को दुनिया के लिए भारत की सबसे मूल्यवान सांस्कृतिक देन बताते हुए कहा कि यह प्राचीन विद्या सभी बाधाओं से परे है और लोगों को स्वास्थ्य, सद्भाव और आंतरिक शांति की दिशा में एक साथ लाती है। इस वर्ष के विषय, ष्स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योगष का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योग शारीरिक शक्ति, मानसिक मजबूती और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे लोग स्वस्थ और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की उन कोशिशों की तारीफ की, जिनसे योग देश के हर कोने तक पहुँचा है और श्योग 365श, श्स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योगश, श्गैर-संचारी रोगों के लिए योगश, श्योग पार्क पहलश और श्100 दिनों का मुफ्त ऑनलाइन योगश जैसी कई पहलों के जरिए यह साल भर चलने वाला जन-आंदोलन बन गया है। इससे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका और मजबूत हुई है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 महज एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के शाश्वत ज्ञान का राष्ट्रीय उत्सव है, जो स्वास्थ्य, सद्भाव और सामूहिक कल्याण के लिए एक वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। वैश्विक भागीदारी में हो रही वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के समन्वित प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस समारोह विश्व भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 210 से अधिक भारतीय दूतावासों की भागीदारी है, जो सामूहिक कल्याण के लिए एक वैश्विक आंदोलन के रूप में योग की भूमिका को दर्शाती है। श्री प्रतापराव जाधव ने योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई मंत्रालय की प्रमुख पहल श्योग 365श की सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने 100 दिनों के निःशुल्क ऑनलाइन योग सत्र के सफल समापन का भी उल्लेख किया और बताया कि 14 जून को आयोजित राष्ट्रव्यापी लाइव योग सत्र में एक साथ चार लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिससे एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। श्री जाधव ने आगे बताया कि संस्कृति मंत्रालय भारत भर के 100 प्रतिष्ठित स्थलों पर विशेष योग समारोहों का आयोजन कर रहा है, जो योग को देश की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और सभ्यतागत पहचान से जोड़ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि कोलकाता और पूरे बंगाल से मिल रही उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया योग के प्रति लोगों के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारी के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित विभिन्न जनसंपर्क पहलों पर भी प्रकाश डाला गया, जिनमें नई दिल्ली में 100 दिवसीय कार्यक्रम, महाराष्ट्र के लोनार में 75 दिवसीय कार्यक्रम, हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में 50 दिवसीय उत्सव और खजुराहो में 25 दिवसीय कार्यक्रम शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख आकर्षण ष्गंगोत्री से गंगासागर - गंगा तट योग यात्राष है, जो गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, हुगली और गंगासागर को जोड़ती है और योग, पर्यावरण जागरूकता, नदी संस्कृति और जनभागीदारी को एक साथ लाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल के राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्री शरदवत मुखोपाध्याय, पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव डॉ. मनोज कुमार अग्रवाल और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी उपस्थित थे। 21 जून से पहले कोलकाता और पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिनमें साइकिलिंग फॉर वेलनेस, स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में योग, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए योग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग, कॉर्पोरेट योग और पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए योग कार्यक्रम शामिल हैं। 19 जून को कोलकाता के ग्यारह स्थानों पर एक विशेष पहल, ष्दौड़ से ध्यानष का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद 20 जून को हुगली नदी के किनारे वंदे योगम और पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कला प्रतियोगिताएं, फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं और जनहित गतिविधियां शामिल होंगी। इस उत्सव में हुगली नदी पर 500 नावों में सामूहिक योग प्रदर्शन भी शामिल होंगे, जो योग और बंगाल की समृद्ध नदी विरासत को उजागर करेंगे। कोलकाता में योग-थीम वाली रोशनी, विशेष पुलों की जगमगाहट और लगभग 3,000 ड्रोनों के साथ एक भव्य ड्रोन शो होगा, जो भारत की योग यात्रा को प्रदर्शित करेगा और महान योग गुरुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों से आग्रह किया कि वे योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समग्र कल्याण के लिए इसे आजीवन अभ्यास के रूप में अपनाएं। नागरिकों को समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेने और योग संगम पोर्टल पर अपने योग कार्यक्रमों को पंजीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह 21 जून को सुबह 5 बजे शुरू होगा। इसमें हजारों लोग व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगें।

एमएसपी से मिलेगा किसानों को सहारा : शिवराज सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार राज्यों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों एवं तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यह खरीद की जाएगी जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उन्हें अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने से राहत मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा लाभ मिला है, जहां ग्रीष्म 2026 सीजन के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृतियों का कुल MSP मूल्य 1,490 करोड़ रुपये से अधिक है। इससे राज्य के दाल और तिलहन उत्पादक किसानों को बड़ा सहारा मिलेगा। श्री शिवराज सिंह द्वारा गुजरात में ग्रीष्म 2026 सीजन के लिए 18,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है। यह खरीद भी PSS के तहत की जाएगी और इसका कुल MSP मूल्य 160 करोड़ रु. से अधिक होगा। इस निर्णय से राज्य के मूंग उत्पादक किसानों को बाजार में बेहतर मूल्य मिल सकेगा। तमिलनाडु के मामले में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए मूंग की खरीद सीमा को 885 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मीट्रिक टन कर दिया है। यानी अतिरिक्त 105 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जाएगी। इस स्वीकृति का कुल MSP मूल्य 8.68 करोड़ रु. होगा जिससे राज्य के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं, हरियाणा में ग्रीष्म 2026 सीजन के लिए 2,115 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है जिसका कुल MSP मूल्य 18 करोड़ रु. से अधिक होगा। यह निर्णय राज्य के किसानों को मूल्य समर्थन देने में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्र सरकार का यह कदम दाल एवं तिलहन उत्पादक किसानों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे उन्हें MSP का लाभ सुनिश्चित होगा और बाजार में कीमतों के दबाव से राहत मिलेगी।

रेलवे द्वारा राख की ढुलाई के लिए हरित पहल

नई दिल्ली। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में रेल नेटवर्क के माध्यम से राख की ढुलाई का बड़े पैमाने पर परिवहन को सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल पर चर्चा की गई। उद्देश्य सरल लेकिन परिवर्तनकारी है: राख की ढुलाई को बिजली संयंत्रों से उद्योगों तक कुशलतापूर्वक पहुँचाना, जहाँ इसका उपयोग सड़कों के निर्माण, ईंटों के उत्पादन, सीमेंट उत्पादन और देश भर में अवसंरचना विकास में किया जा सकता है। बैठक में रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना और श्री रवनीत सिंह बिट्टू भी उपस्थित थे। थर्मल पावर प्लांटों से प्रतिवर्ष लगभग 340 करोड़ टन उड़ने वाली राख उत्पन्न होती है। दशकों से यह भारी राख चिमनियों के आसपास जमा रहती थी। अब भारतीय रेलवे एक हरित पहल के माध्यम से इसे बदल रहा है, जिसके अंतर्गत विशेष कंटेनरों और रेल गलियारों का एक समर्पित लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाया जा रहा है। यह नेटवर्क अपशिष्ट पदार्थ को उसके उत्पादन स्थल से उसके आवश्यक स्थल तक पहुंचाएगा।

स्वामी एवं प्रकाशक मौ. वसी के लिये मुद्रक नुसरत निशान खान द्वारा कौमी गुलदस्ता प्रिंटर्स, विलेज आमवाला, पोस्ट घंघौरा, देहरादून द्वारा, उत्तराखण्ड-248141 से मुद्रित एवं 5, लेन नम्बर 2, नामदेव एन्क्लेव फेस 2, ब्राहम्णवाला, देहरादून उत्तराखण्ड- 248171 से प्रकाशित। सम्पादक-मौ. वसी,
समस्त विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून मान्य होगा। सम्पर्क- 9411112331
हमारे अखबार के ताजा अंक को ऑनलाइन पढ़ने के लिये www.aawamindia.com वेबसाइट पर जायें।
facebook: www.facebook.com/indiaaawam, youtube:www.youtube.com/@aawamindia,
X:www.x.com/aawamindia, Instagram:https://instagram.com/aawamindia